भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष नक्सलवाद की चुनौती

*डॉ. हीरालाल मीणा

सार

भारतीय समाज विविधता से परिपूर्ण समाज है यहां विभिन्न संस्कृतियों जातियों मतों धर्मों वादों प्रति वादों के प्रति आस्था एवं विश्वास रखने वाले मानवीय समुदाय निवास करते हैं। विविधताओं से परिपूर्ण समाज में को एक धागे में पिरोना अत्यंत कठिन कार्य है सांस्कृतिक विविधताओं के साथ यहां राजनीतिक विविधताएं भी उतनी ही व्यापक होती चली जाती हैं इन्हीं की परिणाम स्वरूप भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा उनमें नक्सलवाद एवं अलगाववाद एक प्रमुख समस्या के रूप में आए।

परिचय

भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को अपनाता है जो इसके नागरिकों के लिए बिल्कुल नहीं थी।जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत में अपनाया गया वह विशिष्ट प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था थी यूरोपीय समाजों में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उभर कर आई वह एक निश्चित क्रमबद्ध विकास का परिणाम थी परंतु भारत में उस प्रकार के क्रमबद्ध विकास को न अपनाकर अचानक लोकतांत्रिक व्यवस्था नागरिकों पर थोप दी गई यह नागरिक अब तक ऐसी व्यवस्थाओं में जीवन व्यतीत कर रहे थे जो अत्यंत संकीर्ण तथा अधिनायक वादी प्रवृत्ति की थी ऐसी दशा में नागरिकों को शासक बना देना अत्यंत क्रांतिकारी कदम था।

वस्तुतः लोकतांत्रिक व्यवस्था एक निश्चित विकास क्रम का परिणाम होती है जिसमें सर्वप्रथम धार्मिक लोकतंत्र फिर आर्थिक लोकतंत्र और अंततः राजनीतिक लोकतंत्र का आगमन होता है। परंतु भारत में जिस समय राजनीतिक लोकतंत्र को अपनाया गया उस समय भारतीय जनमानस आर्थिक एवं धार्मिक रूप से अत्यंत संकीर्ण एवं परंपरागत विचारों से शासित हो रहा था जहां लोकतंत्र या लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कोई स्थान नहीं था।

इसी का परिणाम था कि भारतीय जनमानस विभिन्न आर्थिक एवं धार्मिक आधारों पर प्रथक प्रथक वर्गों में बढ़ता चला गया और यहीं से नक्सलवाद और अलगाववाद जैसी समस्याओं का जन्म होता है।

नक्सलवाद एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है जो समाज में अगड़ी एवं प्रभावशाली जातियों एवं वर्गों द्वारा हो रहे शोषण का प्रतिकार करते हुए समताकारी समाज की स्थापना के लिए हिंसक मार्ग को अपनाता है।

वस्तुतः भारत की पश्चिमी बंगाल राज्य जहां स्वतंत्रता से पूर्व जमीदारी प्रथा का प्रचलन था वहां ग्रामीण समाज स्पष्ट है दो वर्गों में बटा हुआ था 1 वर्ग जो जमीदार वर्ग के रूप में पहचाना जाता था वह आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली वर्ग था वही दूसरा वर्ग शोषित एवं पिछड़ा हुआ वर्ग जो खेतिहर मजदूरों के रूप में था इन्हीं खेतिहर मजदूरों के भूमि पर अधिकार एवं कृषि की स्वायत्तता को लेकर उपजे संघर्षों की परिणिति के रूप में बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से इस विचारधारा का जन्म हुआ।

वही अलगाववाद एक ऐसी विचारधारा का पक्ष पोषण करता है जो भारतीय संघात्मक एवं लोकतंत्रात्मक व्यवस्था से ही हो जाना चाहते हैं इस व्यवस्था में समाज के ऐसे वर्ग और समुदाय जो अपने आप को पृथक महसूस करते हैं और अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना चाहते हैं वे समय-समय पर भारतीय शासन व्यवस्था से पृथक हो जाने की मांग करते रहे हैं यह स्वतंत्रता के पश्चात से ही दक्षिण भारतीय राज्यों द्वारा द्रवीणाम धर्म की मांग के रूप में उभरी थी साथ ही यह समय-समय पर पंजाब प्रांत में खाली स्थान की मांग के रूप में तथा पूर्वोत्तर में छोटे-छोटे जनजाति वर्गों द्वारा प्राप्त हो जाने की मांग के रूप में दिखाई देती है प्रारंभ में यह मांग वैचारिक आधार पर प्रस्तुत की गई थी परंतु कालांतर में इनमें से अधिकांश ने हिंसक एवं उग्र रास्ता अपना लिया जो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती बनकर उभरी।

अध्ययन का महत्व

वर्तमान समय में भारतीय लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियों में नक्सलवाद एवं अलगाववाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंतरिक चुनौतियां हैं इन चुनौतियों की वजह से भारतीय लोकतंत्र अपनी परिपक्वता को प्राप्त नहीं हो पा रहा है साथ ही इनकी वजह से आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना सरकार के लिए अत्यंत कठिन होता चला जा रहा है क्योंकि इन विचारधाराओं का प्रभुत्व ऐसे क्षेत्रों में है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं अतः प्रस्तुत शोध पत्र उन कारणों को खोजने का प्रयास करता है जिनकी वजह से यह चुनौतियां उभर आई है।

इन चुनौतियों के समाधान के लिए इनकी प्रकृति एवं इनके उदय के लिए उत्तरदायी कारणों को खोजना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तक समस्या के कारणों को नहीं समझा जाएगा इनका समाधान किया जा सकता संभव नहीं होगा।

प्रस्तुत शोध पत्र इन आंतरिक चुनौतियों के कारणों को खोजने का प्रयास कर रहा है जिनकी माध्यम से शासन व्यवस्था इन चुनौतियों के लिए उपचारात्मक कदम उठा सके।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य उन कारणों की खोज करना है जिनकी वजह से समाज में नक्सलवाद एवं अलगाववाद का जन्म हुआ।

इस प्राथमिक उद्देश्य के साथ ही शोध पत्र के कुछ गौर उद्देश्य भी हैं जो निम्नलिखित हैं।

1. उन वर्गों की सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करना जहां इस प्रकार की चुनौतियां उभरकर आई।
2. समाज में आर्थिक संसाधनों के वितरण में व्याप्त असमानता का विश्लेषण करना।
3. समाज में शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों की समानता का अध्ययन करना।
4. कृषि कृषक एवं कृषि भू भाग से जुड़ी हुई समस्याओं का अध्ययन करना जिन्होंने इस प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया।
5. ऐसे उपायों की खोज करना जिन से ऐसे वर्गों को भारतीय समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

शोध का रीति विधान

प्रस्तुत शोध पत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही प्रकार की समंक सूचनाओं पर आधारित है।

प्राथमिक समंक विभिन्न विश्वविद्यालयों की संख्या सदस्यों से प्रश्नावली या भरवा कर प्राप्त किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ राज्य की चार जिलों से 400 व्यक्तियों से प्रश्नावली भरवा कर प्रभावित वर्ग के समक्ष एकत्रित करने का प्रयास किया गया है।

द्वितीयक समंक भारत सरकार की विभिन्न रिपोर्टों जिसमें गृह मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन सम्मिलित हैं के आधार पर सूचना एकत्रित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट से भी आवश्यक समंक लिए गए हैं। इसके साथ-साथ प्रभावित राज्यों की गृह विभागों की विभिन्न रिपोर्टों को भी आधार बनाया गया है।

समंक विश्लेषण के लिए किसी विशिष्ट सांख्यिकी पद्धति को प्रयोग में ना लाकर शरद लिखित रूप से संबंधों के वर्गीकरण एवं सारणीयन के माध्यम से विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

प्राप्तियां

शोध पत्र के लिए किए गए अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष वर्तमान में सबसे बड़ा संकट नक्सलवाद की समस्या तथा अलगाववाद के रूप में उभरकर सामने आता है।

भारत में नक्सलवादी गतिविधियों का क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है वर्तमान में यह आंध्र प्रदेश तेलंगाना बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश पश्चिमी बंगाल तमिलनाडु उत्तराखंड केरल और कर्नाटक राज्यों में फैल चुका है। इससे स्पष्ट होता है कि नक्सलवादी विचारधारा का प्रसार भारत के आधे से अधिक भूभाग पर हो चुका है तथा गृह मंत्रालय के विभिन्न प्रतिवेदन ओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत के 9 राज्यों के 106 जिले नक्सलवाद से अत्यधिक रूप में प्रभावित हैं जहां सामान्य जीवन यापन एवं जीविकोपार्जन की

गतिविधियों को संचालित करना सामान्य जनमानस के लिए अत्यंत कठिन होता जा रहा है।

प्रारंभिक दौर में यह देखा गया कि नक्सलवादी गतिविधियां मार्क्सवादी विचारधारा का पक्ष पोषण करने वाली राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रेरित की जा रही थी परंतु पिछले कुछ वर्षों में इसमें बड़ा नाटकीय परिवर्तन हुआ है और कहीं-कहीं ऐसा देखने को मिला है कि विदेशी गुप्तचर एजेंसियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नक्सलवादी संगठनों से संपर्क बनाए हुए हैं।

नक्सलवादी विचारधारा हिंसा को प्राथमिकता देती है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा को एक साधन के रूप में प्रयोग में लाती है इसके द्वारा की गई हिंसा के द्वारा भारतवर्ष में बड़े पैमाने पर अराजक स्थितियां उत्पन्न हुई है हिंसक गतिविधियों की जनता को हम निम्न सारणी से समझ सकते हैं।

नक्सलवादी गतिविधियों की घटनाएं

वर्ष	घटनाएं
2012	1415
2013	1136
2014	1091
2015	1088
2016	1048
2017	908

सारणी के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि नक्सलवादी गतिविधियों की प्रवृत्ति में गिरावट आती जा रही है। गिरावट का यह अनुक्रम सरकारी प्रयासों एवं जनमानस में हिंसा के प्रति विचारों में हुए परिवर्तन के कारण हुआ है।

नक्सलवादी गतिविधियों में मारे गए व्यक्तियों की संख्या

वर्ष	मौतें
2012	415
2013	397
2014	310
2015	226
2016	278
2017	263

उपरोक्त सारणी में नक्सलवादी घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है।सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नक्सलवादी घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या में प्रभावी रूप से कमी आती जा रही है परंतु यह अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है।

शोध पत्र तैयार करते समय किए गए अध्ययन से एक नवीन प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई देती है प्रभावित क्षेत्रों में राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नक्सलवादी संगठनों से राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों द्वारा संपर्क बनाया जाता रहा है। यह स्थिति भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकती है

वहीं दूसरी ओर यदि हम अलगाववाद की बात करें तो अलगाववादी गतिविधियों का केंद्र पूर्वोत्तर के राज्य बने हुए हैं। नागालैंड मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम में अलगाववादी गतिविधियां अपने चरम पर है तथा यह अपनी जनजातीय विशेषताओं के प्रति अत्यधिक जागरूक होने के कारण अपने पृथक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। सरकारी प्रयासों के माध्यम से अलगाववादी गुटों से समझौता वार्ताएं लंबे समय से चली आ रही है जिनके कुछ सकारात्मक परिणाम भी वर्तमान समय में दिखाई देने लगे हैं पूर्वोत्तर में हो रही हिंसक गतिविधियों में प्रभावी कमी आती जा रही है।

सुझाव

नक्सलवाद एवं अलगाववाद दो प्रथक प्रथक समस्याएं हैं जिनका प्रसार क्षेत्र भी भारत के भू भाग पर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है परंतु इनकी जन्म के पीछे विद्यमान कारणों में कहीं ना कहीं समानता दिखाई देने लगती है। दोनों ही समस्याएं भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करती हैं इन चुनौती का सामना करने के लिए भारत सरकार राजनीतिक दलों तथा सामान्य जन द्वारा निम्न प्रयास किए जाने चाहिए।

1. प्रभावित क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है कि शिक्षा का स्तर पर्याप्त निम्न स्तर पर है अतः हमें प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के आधार ढांचे को सुदृढ़ करना होगा तथा साक्षरता दर में प्रभावी रूप से सुधार लाना होगा।
2. प्रभावित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की कमी दिखाई पड़ती है रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की वजह से नवयुवक दिग्भ्रमित हो जाता है और वह इस प्रकार की हिंसक गतिविधियों से जुड़ता चला जाता है अतः हमें नए नए रोजगार के अवसरों को सृजित करने को प्राथमिकता देनी होगी।
3. प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक असमानता व्यापक पैमाने पर दिखाई पड़ रही है अतः बहुसंख्यक जन समुदाय के मस्तिष्क में एक विचार जन्म कर गया है कि जब तक वे पूंजीपतियों एवं भू पतियों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्य करते हुए उनकी संपत्ति ने हड़प ले तब तक आर्थिक पराधीनता से मुक्ति नहीं प्राप्त की जा सकेगी। अतः

सरकार को चाहिए कि वह प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाओं के माध्यम से निर्धन वर्ग को अतिरिक्त क्रय शक्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास करें।

4. नक्सलवाद एवं अलगाववाद दोनों ही चुनौतियों का प्रसार जिन क्षेत्रों में दिखाई देता है वह जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं इन जनजातियों के मन में सदैव से एक शंका बनी हुई है कि विकास की प्रक्रिया के द्वारा उनकी विशिष्ट पहचान को समाप्त कर दिया जाएगा।ऐसी स्थिति में भी सदैव भय और असुरक्षा के वातावरण में जीवन जी रहे हैं। अतः सरकार को चाहिए कि सरकार इन जनजातियों के परंपरागत अधिवासों को संरक्षित करते हुए इनको आश्वस्त करे कि उनकी विशिष्ट पहचान को बनाए रखा जाएगा।
5. ऐसा देखने में आया है कि इन क्षेत्रों में खनिज संपदा के दोहन के लिए बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई है जिसमें बाहरी व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है तथा स्थानीय युवाओं की पूर्ण तरह उपेक्षा की गई है अतः सरकार इन उद्योगों में स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए प्रभावी रूप से प्रयास करें जिससे यह लोग समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें।
6. यह क्षेत्र इतनी अधिक संवेदनशील है कि इनमें सरकार को किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए सरकार को यहां स्वयं सहायता समूह तथा सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से शांति बहाली के प्रयास करने चाहिए।

निष्कर्ष

भारतीय लोकतंत्र को यदि हमें सशक्त एवं सफल बनाना है तो हमें विविधताओं के मध्य एकता के सूत्रों को ढूंढना होगा हमें परस्पर सामंजस्य एवं सहयोग की भावना से प्रेरित हो समाज के सभी वर्गों को साथ लाना होगा।

नक्सलवाद एवं अलगाववाद बिल्कुल विशिष्ट प्रकार की समस्याएं हैं अतः उनके समाधान के लिए किए जाने वाले प्रयास भी विशिष्ट होने चाहिए। स्थानीय व्यक्तियों में विश्वास उत्पन्न किया जाना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र केवल अभिजात वर्ग का लोकतंत्र नहीं है वह समाज के निचले पिछड़े और उपेक्षित वर्ग को भी उचित स्थान उपलब्ध कराता है। शोध पत्र में किए गए अध्ययन से यह उभर कर आता है कि दोनों ही प्रकार की समस्याएं अशिक्षा बेरोजगारी निर्धनता राजनीतिक सांस्कृतिक करण का अभाव संवाद हीनता से उत्पन्न हुई है अतः सरकार को इन कारणों के प्रति संवेदनशील रुख अपनाते हुए इन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

यदि हमें एक आदर्श शासन व्यवस्था एवं सफल लोकतंत्र को स्थापित करना है तो हमें इन चुनौतियों का शक्ति आधार पर नहीं अपितु भ्रातृत्व बंधुत्व की विचारधारा के आधार पर समाधान निकालना होगा।

*व्याख्याता
राजकीय महाविद्यालय
करौली (राज.)

संदर्भ ग्रंथ

1. राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट वर्ष 2010 से 2020 तक
2. भारत सरकार के गृह मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010 से 2020 तक
3. छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल कि गृह विभागों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010 से 2020
4. राजस्थान पत्रिका
5. दैनिक भास्कर
6. भारतीय शासन एवं राजनीति बी एल फडिया साहित्य भवन प्रकाशन
7. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी के विभिन्न प्रकाशन
8. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया के विभिन्न प्रकाशन